भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1552
26.07.2016 को उत्तर के लिए

गंगोत्री हिमनद

1552. श्री कल्याण बनर्जी :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगोत्री हिमनद का पीछे हटना गंगा नदी के जलस्तर में कमी का एक प्रमुख कारण है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास पीछे हट रहे हिमनदों के संबंध में कोई अध्ययन रिपोर्ट है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) हिमालयन क्षेत्र में बर्फ निर्माण में असंतुलन को रोकने तथा हिमनदों के पिघलने की दर के संबंध में सरकार की क्या कार्य योजना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री अनिल माधव दवे)

(क) राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान के अनुसार, गंगोत्री हिमनद के पीछे हटने से गंगा नदी के प्रवाह पर अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा । गंगा नदी मुख्य जल-उदगम क्षेत्र में भी अपने जल के लिए पूर्णत: हिमनदों पर निर्भर नहीं है । जैसे-जैसे हम अधोधारा की ओर चलते हैं तो बर्फ की प्रतिशतता और हिमनद-युक्त योगदान में प्रगामी रूप से कमी मिलती है । वर्षा जल और उप-सतही प्रवाह, हरिद्वार में गंगा नदी के प्रवाह में 70% से अधिक योगदान करते हैं ।

(ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एण्ड सीसी) के साथ एक सहयोगपूर्ण परियोजना में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने वर्ष 2004 से 2007 के दौरान भारतीय उपग्रह आंकड़ों का प्रयोग करते हुए हिमालयी हिमनदों का मानचित्रण किया है । इस अध्ययन से पता चलता है कि कारकोरम प्रदेश सहित हिमालय और सीमापार-हिमालय क्षेत्र समेत सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में 75,779 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र में 34,919 हिमनद हैं । इसके अलावा, इसरो ने वर्ष 2000-01 से 2010-11 तक उपग्रह आंकड़ों का प्रयोग करके हिमालयी क्षेत्र में 2018 हिमनदों के आगे खिसकने और पीछे हटने की निगरानी की है । इस अध्ययन से पता चलता है कि 87% हिमनदों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 12% हिमनद पीछे हटे हैं और 1% हिमनद आगे खिसके हैं । अंतरिक्ष विभाग द्वारा वित्त पोषित "जलवायु परिवर्तन के कारण अंतरिक्ष आधारित सूचनाओं और प्रभाव मूल्यांकन का प्रयोग करके हिमालयी हिमांक मंडल का एकीकृत अध्ययन" शीर्षक से एक नई परियोजना के भाग के रूप में हिमालयी हिमनदों की और अधिक निगरानी की जा रही है ।

(ग) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत राष्ट्रीय हिमालयी पारि -प्रणाली सततता मिशन (एनएमएसएचई) में निगरानी तंत्र की स्थापना, समुदाय आधारित प्रबंधन के संवर्धन, मानव संसाधन विकास और क्षेत्रीय सहयोग के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से हिमालयी हिमनदों और पर्वत पारि-प्रणालियों को सतत बनाने और सुरक्षित करने के लिए संरक्षण उपाय करना शामिल है । एनएमएसएचई के अंतर्गत की गई प्रमुख पहलों में हिमालयी कृषि, पारम्परिक ज्ञान प्रणालियों, वन संसाधन और पौध विविधता तथा प्राणि-जात और वन्यजीव पर्यावासों के संबंध में चार विषयगत कार्य बलों का सृजन शामिल है । इसके अलावा, सात हिमालयी राज्यों नामश: जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और मेघालय में राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र स्थापित किए गए हैं ।

*****